



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2001/ भाद्र 30, 1923

No. 475]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2001/BHADRA 30, 1923

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001

सा.का.नि. 682(अ).— जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परित्कार तथा आर्थिक अपवर्धन की रोक धाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा आस्ट्रेलिया गणराज्य सरकार के मध्य संबद्ध अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 के पैरा-2 द्वारा यथा अपेक्षित अभिसमर्थन के लिखतों के आदान-प्रदान के तीस दिन के पश्चात दिनांक 5 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त होगा ।

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961§1961 का 43§ की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जासगा ।

आयकर

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार  
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार  
और

ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार  
के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के  
लिए एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक कार्यक्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सौंधदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के  
निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय किसी सौंधदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण  
की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त आयों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा अदा  
की जाने वाली मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ पूंजी की मूल्यवृद्धि पर करों सहित  
कुल आय अथवा आय के तत्त्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।
3. जिन मौजूदा करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

§ क § ऑस्ट्रिया में :

§ i § आयकर § दी आइनकोमेन्स्टेर § ;

§ ii § निगम कर § दी कार्परशाफ्ट्स्टेर § ;

जिसे इसके बाद ऑस्ट्रियाई कर कहा जाएगा ;

§ ख § भारत में :

आयकर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 § के अधीन लगाया गया आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;

जिसे इसके बाद भारतीय कर कहा जाएगा ।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्कतः समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने करधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

§ क § "आस्ट्रिया" पद से अभिप्रेत है आस्ट्रिया गणराज्य ;

§ ख § "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें इसके राज्य-क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;

§ ग § "एक सौविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा सौविदाकारी राज्य" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार आस्ट्रिया अथवा भारत अभिप्रेत है ;

§ घ § "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है :

§ i § आस्ट्रियाई कर के संबंध में कैलेंडर वर्ष ;

§ ii § "भारतीय कर" के संबंध में अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष ;

§ ङ § "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार आस्ट्रियाई कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है, जिनके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जहां उन करों के संबंध में लगाए गए अर्धदंड की घोषणा है ;

- § च § "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी और कोई दूसरी सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रकृत करधान कानूनों के तहत एक कराधेय ईकाई माना जाता हो ;
- § छ § "कम्पनी" पद से ऐसा कोई निगमित निकाय अथवा ऐसी कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रकृत करधान कानूनों के तहत एक कम्पनी अथवा निगमित संस्था माना जाता हो ;
- § झ § "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :
- § i § आस्ट्रेलिया में : संघीय वित्त मंत्रालय अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- § ii § भारत में : केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय § राजस्व विभाग § अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- § ज § "राष्ट्रक" पद से अभिप्रेत है :
- § i § एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;
- § ii § कोई ऐसा कानूनी व्यक्ति मागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रकृत कानूनों से प्राप्त होती है ;
- § ट § "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थान के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कर्तों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिनपर यह अभिसमय लागू होता है ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रवच-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य तथा उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा उसका कोई प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति

शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित उसके खेतों अथवा फ़ूजी से प्राप्त ऋण के बारे में ही उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों सौविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

॥क॥ उसे उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर ॥महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र॥ है ;

॥ख॥ यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

॥ग॥ यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

॥घ॥ यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी एक का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों सौविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें उसका व्यक्तिगत प्रबंध-स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सके जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध-स्थान स्थित हो, तो सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

#### अनुच्छेद - 5

#### स्थायी संस्थापन

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :-

॥क॥ प्रबन्ध का कोई स्थान ;

॥ख॥ कोई शाखा ;

- ॥ ग ॥ कोई कार्यालय ;
- ॥ घ ॥ कोई कारखाना ;
- ॥ ङ - ॥ कोई कार्यशाला ;
- ॥ च ॥ कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई सदान अथवा प्रकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- ॥ छ ॥ कोई विक्रय केन्द्र ;
- ॥ ज ॥ अन्य व्यक्तियों हेतु भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति का कोई भाण्डागार; और
- ॥ झ ॥ कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा इनसे संबंधित पर्यक्षी कार्यकलाप जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप वैसी ही अथवा संयोजी परियोजना, स्थल अथवा कार्यकलाप छह माह से अधिक की अवधि तक जारी रहते हों ।

3. किसी उद्यम के लिए यह माना जाएगा कि उसका किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है और वह उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है यदि वह उस राज्य में खनिज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण या दोहन के संबंध में सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है अथवा उसके लिए या उसमें प्रयुक्त होने वाले संयंत्र और मशीनों को किराए पर सप्लाई करता है ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :-

- ॥ क ॥ किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- ॥ ख ॥ केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- ॥ ग ॥ किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- ॥ घ ॥ किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना पत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- ॥ ङ - ॥ उद्यम के लिए प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

॥ च ॥ उप-पैराग्राफ ॥ क ॥ से ॥ ड ॥ तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्यकलापों के संयोजनों हेतु व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रस-रसाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परामर्शस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ लागू होता हो, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, तब उस उद्यम का प्रथमोत्तिष्ठित राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि -

॥ क ॥ उसे उस राज्य में उद्यम की ओर से सौंपाएं निष्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियाँ पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाया ;

॥ ख ॥ ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में आमतौर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो ;

॥ ग ॥ वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से उस उद्यम के लिए ही अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने वाले अथवा उस उद्यम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक-समान नियंत्रण के अधीन आने वाले उद्यम अथवा अन्य उद्यमों के लिए आमतौर से आईर प्राप्त करता रहता हो ।

6. किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से एक स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हों । किन्तु, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतया अथवा प्रयः पूर्णतया स्वयं उस उद्यम की ओर से उस उद्यम और अन्य उद्यमों के लिए किए जाते हों अथवा उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, किसी सौविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, पुनर्बीमा के मामले छोड़कर, दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में प्रिमियम एकत्र करता है अथवा किसी ऐसे स्वतंत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, वहां स्थित जोसिमों का बीमा करता है।
8. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक सौविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे सौविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य में कोई भी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा में कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

### अनुच्छेद - 6

#### अचल सम्पत्ति से आय

1. एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी की दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति जिसमें कृषि अथवा वन-सम्पत्ति भी शामिल है से अर्जित आय पर उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस सौविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे-

अचल सम्पत्ति के अक्सादन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और खानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और सनिज भंडार, खेत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नावें और विमान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।



## अनुच्छेद - 7

## कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन से प्राप्त होंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जिनके होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसमें इस प्रकार संचय किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे चाहे वे संचय उस राज्य में किए जाएं जहां उक्त स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा कहीं अन्यत्र किए जाएं और इस कटौती की अनुमति उस संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अनुसार दी जाएगी जहां उक्त स्थायी संस्थापन स्थित हो। तथापि उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के मुख्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों, जानकारीयों या अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य उसी तरह की अदायगियों के तौर पर अथवा निर्धारित विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के तौर पर अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, उक्त स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के तौर पर अदा की गई वस्तुविक्रय संचयों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर) राशिओं, यदि कोई हो, के बारे में इस तरह की किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के मुख्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारीयों या अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य इसी तरह की अदायगियों के

तौर पर अथवा निर्धारित वर्गों के सेवाओं के लिए या प्रबंध के लिए कमीशन के तौर पर अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, उक्त उद्यम के मुख्यालय या इसके किसी भी अन्य कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के तौर पर प्रभाविता धनसहायियों § वास्तविक सचों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर पर किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

4. कोई लाभ केवल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा फ्य-वस्तुएं सहीदी गई हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों के तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहां आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

#### अनुच्छेद - 8

#### जहाजरानी और वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी ऐसे उद्यम द्वारा जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा फ्य-वस्तुओं के परिवहन में प्रयुक्त आधानों § आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलरों और अन्य उपकरणों सहित के प्रयोग रख-रखाव अथवा उन्हें किराए पर देने से प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि आधानों का केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर ही प्रयोग न किया जाए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों या वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों या वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी फूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन फेजेन्सी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

## अनुच्छेद - 9

## सम्बद्ध उद्यम

1. जहां :-

- { क } एक सौविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सौविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- { स } वही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में और दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेता है;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न होती हैं, जैसे स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, ऐसे मामले में ऐसे कोई भी लाभ जो, उन शर्तों के नहीं होने की हालत में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जाएंगे और वे तदनुसार कराधेय होंगे ।

2. जहां एक सौविदाकारी राज्य उस राज्य के उद्यम के लाभों में उन लाभों को शामिल करता है और तदनुसार उस पर कर लगाता है, जिस पर दूसरे सौविदाकारी राज्य के उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार शामिल लाभ वे लाभ हैं जो कि प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें वे शर्तें होतीं जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तो उस दूसरे राज्य को उन लाभों में उसमें प्रचार्य कर की राशि के लिए समुचित समायोजन करना होगा । ऐसे समायोजन का निर्धारण करने के लिए इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को भी ध्यान में रखना होगा और सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो, तो एक दूसरे से परामर्श करेंगे ।

## अनुच्छेद - 10

## लभ्यांश

1. एक सौविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लभ्यांश उस दूसरे राज्य में करायेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लभ्यांशों पर उस सौविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लभ्यांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, किन्तु यदि लभ्यांशों का हितभागी स्वामी दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लभ्यांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

यह पैराग्राफ उन लभ्यों के बारे में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लभ्यांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लभ्यांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लभ्य की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हैं और इसमें अन्य निर्गमित अधिकारों से प्राप्त आय भी शामिल है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लभ्यांशों का हितभागी स्वामी, जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं संपन्न करता है जिसकी लभ्यांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है और जिस धारणाधिकार के संबंध में लभ्यांश अदा किए जाते हैं वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 14 जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक सौविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सौविदाकारी राज्य से लभ्य अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लभ्यांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लभ्यांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लभ्यांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से

संबंधित है और न ही वह कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ संबंधी कर लगाया जाये अदा किए गए लाभों अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो हों ।

### अनुच्छेद - 11

#### न्याज

1. एक संधिदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संधिदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले न्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. किन्तु, इस प्रकार के न्याज पर उस संधिदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि न्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संधिदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार से लगाया जाने वाला कर न्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी,
  - §क§ एक संधिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले न्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है ;
    - §i§ दूसरे संधिदाकारी राज्य की सरकार, उसका राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्रधिकरण ; अथवा
    - §ii§ अन्य संधिदाकारी राज्य का सेण्ट्रल बैंक ; अथवा
    - §iii§ भारत के मामले में एक्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इण्डिया भी ; अथवा
    - §ii/§ आस्ट्रिया के मामले में आस्टेरिचिश कांट्रोल बैंक ए0जी0 भी ;
  - §ख§ एक संधिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले न्याज पर उस संधिदाकारी राज्य में उस राज्य की अनुमोदित सीमा तक कर से छूट प्राप्त होगी यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है । §उप-पैराग्राफ "क" में संदर्भित व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति§ जो दूसरे संधिदाकारी राज्य का निवासी हो बशर्ते कि प्रामोदित संधिदाकारी राज्य द्वारा हर संबंध में उस संव्यवहार का अनुमोदन कर दिया गया हो जिसके कारण ऋण-दाया उत्पन्न हुआ है ।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "न्याज" शब्द से अभिप्रेत है, प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं हो और चाहे उसे ऋणकर्ता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो, और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियाँ, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रिमियम और पुरस्कार भी शामिल है। क्लिप से की गई अदायगी के लिए अर्धदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए न्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि न्याज का हितभागी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें न्याज प्रेक्षित हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण दावे के बारे में न्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो, ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. न्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब न्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य हो। किन्तु जहाँ न्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर न्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का न्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा गठन किया जाता है, तो इस प्रकार का न्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन का निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ न्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई न्याज की रकम उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए न्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्धित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का समयक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

## अनुच्छेद - 12

## रायटियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक सौविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायटियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. तथापि, इस प्रकार की रायटियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सौविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु यदि रायटियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी हो, तो इस प्रकार से लगाया जाने वाला कर रायटियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायटियाँ" शब्द का अभिप्राय है - सिनेमा फिल्मों और आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के लिए प्रसारण के संबंध में फिल्मों अथवा टेपों सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कॉपीराइट, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला या प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियाँ ।
4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से प्रबंधकीय तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी सेवाओं अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में अदायगियाँ करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को दी जाने वाली कोई भी राशि अभिप्रेत है ।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायटियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे सौविदाकारी राज्य में जिसमें रायटियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हों, वहाँ पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस अन्य राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा

सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें उद्भूत हुईं तभी मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें अदा करने की जिम्मेदारी निभायी गई हो, और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें उस राज्य में उद्भूत हुईं मानी जाएंगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हो।

7. जहां, अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण प्रवृत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

#### अनुच्छेद - 13

#### पूंजीगत अभिलक्षण

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलक्षणों पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलक्षणों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलक्षणों



पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी<sup>1</sup> को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन<sup>2</sup> अर्थात् अथवा पूर्ण उद्यम के साथ<sup>3</sup> अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलम्भ भी शामिल हैं, उस पर दूसरे राज्य में भी कर लग सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिवहन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है ।

4. किसी फेसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी के शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर उस राज्य में कर लगाया जाएगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न करों भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

#### अनुच्छेद - 14

##### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यवसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यक्षेत्रों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब फेसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में करलेय होंगे :-

॥क॥ यदि उसे अपने कार्यक्षेत्रों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

§ स § यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसमें ठहरने की अवधि अथवा अवधियों किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक हो, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उसे दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद से स्वतंत्र, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य कलाप तथा चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, वंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं ।

#### अनुच्छेद - 15

##### परस्परव्यक्ति वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल प्रयोजित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा यदि :-

§ क § प्राप्तकर्ता किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिनों की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है; और

§ स § परिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

§ ग § परिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम्य द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित फ्रेट अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

## अनुच्छेद - 16

## निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो अन्य सौविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की दौसयत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

## अनुच्छेद - 17

## मनोरंजनकर्ता अथवा सिलाड़ी

1. अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी सिलाड़ी के रूप में दूसरे सौविदाकारी राज्य में उसके इस प्रकार के वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी सिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की दौसयत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या सिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो आंशु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस सौविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा सिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा सिलाड़ी द्वारा जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी हो उसके द्वारा अन्य सौविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय केवल उस स्थिति में कराधेय होगी, यदि अन्य सौविदाकारी राज्य में ऐसे क्रियाकलापों की प्रथमोल्लिखित सौविदाकारी राज्य की लोकनिधियों द्वारा पूर्णतया अथवा अंशतः सहायता की जाती हो जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्रधिकरण भी शामिल हैं ।

4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी सिलाही द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा सिलाही को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अन्य संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि उस अन्य व्यक्ति की उस अन्य राज्य की लोक नियतियों द्वारा पूर्णतया अथवा अंशतः सहायता की जाती हो, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा अधिकरण भी शामिल हैं।

#### अनुच्छेद - 18

##### पेंशन तथा वार्षिकियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. "पेंशन" पद से फिजली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है।

3. "वार्षिकी" पद से जीवन-काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या अधिनिश्चित समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के करार के अंतर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है।

#### अनुच्छेद - 19

##### सरकारी सेवा

1. §क§ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय अधिकरण द्वारा उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय अधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन से भिन्न परिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

§ख§ तथापि, ऐसे परिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा यदि सेवाएं उस अन्य राज्य में की जाती हों और व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी हो; जो

§i§ उस राज्य का एक रहिद्वक हो; जो

§ii§ मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य के विदेशी व्यक्ति के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर अन्य संविदाकारी राज्य में भी लागू होंगे ।

3. § क § किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण द्वारा सृजित नियमों द्वारा अथवा उसमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा ।

§ ख § तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा यदि उक्त व्यक्ति उस दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रक हो ।

4. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पेंशनों तथा पारिश्रमिक पर लागू होंगे ।

### अनुच्छेद 20

#### विद्यार्थी

1. एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो अन्य संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो उस दूसरे राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए मौजूद रहता है उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट दी जाएगी :

§ क § उस दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए की गई अदायगियां ; और

§ ख § उस दूसरे संविदाकारी राज्य में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक जो वह किसी बारह महीने की अवधि अथवा अवधियों में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिनों की अवधि के लिए करता हो, बशर्ते कि ऐसा रोजगार उसके अध्ययन अथवा प्रशिक्षुता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल उसी अवधि तक ही लागू रहेंगे जो ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण पूरा करने हेतु व्यावहारिक अथवा प्रचलित हों, परन्तु किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी राज्य में पहली बार पहुंचने की तारीख से लगातार पंच वर्षों से अधिक इस अनुच्छेद के लाभ नहीं मिलेंगे ।

### अनुच्छेद 21

#### प्रध्यापक, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रध्यापक अथवा अध्यापक, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो शिक्षण अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों ही प्रयोजनों हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्था में जाता है तो उसे उस दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से उस अवधि तक ऐसे शिक्षण अथवा शोध-कार्य पर किसी भी परिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो ।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोध-कार्य मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो ।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "अनुमोदित संस्थान" का अर्थ ऐसी संस्था से है, जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

### अनुच्छेद - 22

#### अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल अथवा सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से

कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे सौविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

### अनुच्छेद 23

#### दोहरे करधान का अपकरण

1. दोनों सौविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रकृत कानून संबंधित राज्यों में आय पर करधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों में जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत प्रवधान किए जाएं।

2. आस्ट्रिया के मामले में, दोहरे करधान का अपकरण निम्नानुसार किया जाएगा :-

§क§ जहां आस्ट्रिया का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहां आस्ट्रिया उप-पैरा §स§ और §ग§ की शर्तों के अधीन ऐसी आय पर कर से छूट प्रदान करेगा ;

§स§ जहां आस्ट्रिया का कोई निवासी आय की ऐसी मदें प्राप्त करता है जिस पर अनुच्छेद 10, 11, 12 के पैराग्राफ 2, अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4 और 5 और अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां आस्ट्रिया उस निवासी की आय से भारत में अदा किए गए कर की राशि के बराबर की राशि की कटौती करने की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती आयकर के उस अंश से, जो कटौती किए जाने से पूर्व संगणित की जाती है, अधिक नहीं होगी जो आय की ऐसी मदों से उद्भूत होती है जो भारत में प्राप्त की जाती है ; और

§ग§ जहां पर इस अभिसमय के किसी भी उपबंध के अनुसार आस्ट्रिया के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय पर आस्ट्रिया में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां आस्ट्रिया ऐसे निवासी की बाकी आय पर कर-राशि की गणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

3. भारत के मामले में, दोहरे करधान का अपकरण निम्नानुसार किया जाएगा :-

§ क § जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार आस्ट्रिया में कर लगाया जा सकता है वहां भारत उस निवासी की आय से आस्ट्रिया में अदा किए गए आयकर के बराबर की राशि की कटौती की अनुमति देगा चाहे वह प्रत्यक्ष तौर पर अदा किया गया हो अथवा स्रोत पर कर कटौती द्वारा । ऐसी राशि आयकर के उस अंश से, जो कटौती दिए जाने से पूर्व संगणित की जाती है, अधिक नहीं होगी जो उस आय से उद्भूत होती है जिस पर आस्ट्रिया में कर लगाया जा सकता है ; और

§ ख § जहां पर इस अभिसमय के किसी भी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय पर भारत में कर से छूट प्राप्त है, वहां भारत ऐसे निवासी की बाकी आय पर कर-राशि की गणना करते समय छूट-प्राप्त आय को भी ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक सौविदाकारी राज्य के राष्ट्रकों पर विशेषकर निवास के संबंध में दूसरे सौविदाकारी राज्य में ऐसा कोई करधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस करधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रकों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी एक अथवा दोनों सौविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे सौविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई करधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यक्षमों को करने के लिए लागू होने वाले करधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक सौविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे सौविदाकारी राज्य के निवासियों को करधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है ।



3. ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्योग द्वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायस्वे तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्योग के कर्षण्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया है।

4. एक सौविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे सौविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कर्षण्य से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपबंध प्रत्येक किस्म और विवरण के कर्षों पर लागू होंगे।

#### अनुच्छेद - 25

##### परस्पररक्षक व धर विधि

1. जहाँ कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों सौविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के देशीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों का ध्यान किए बिना मामला उस सौविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 5 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस सौविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है।

यह मामला उस कार्यवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कर लगाया गया है जो इस अभिसमय में नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कर्षण्य के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं

है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें परस्पर सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कथान को दूर करने के लिए परस्पर विचार कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, जिसमें स्थान उनके तथा उनके प्रतिनिधियों के संयुक्त आयोग के माध्यम से पत्र व्यवहार भी किया जाना भी शामिल है।

#### अनुच्छेद - 26

##### सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना {दस्तावेजों सहित} का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों {जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं} को प्रकट किया जाएगा जो उन कर्तव्यों का निर्धारण अथवा उनकी कसूती करने, उनके बारे में प्रवर्तन अथवा उससे संबंधित अपिलों का निर्धारण करने में शामिल हों, जो अभिसमय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

{क} उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपयय करना ;

§ ख § ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हैं ।

§ ग § ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिनसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्वजनिक नीति §आर्डर पब्लिक§ हो ।

#### अनुच्छेद - 27

#### राजनयिक और कौंसुली कार्य-कलाप

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के विदेशाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

#### अनुच्छेद - 28

#### प्रवृत्त होना

इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन प्रपत्रों का आदान-प्रदान यथा संभव नई दिल्ली में शीघ्र किया जाएगा ।

2. यह अभिसमय अनुसमर्थन प्रपत्रों के आदान-प्रदान किए जाने के तीस दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा और अभिसमय के उपबंध निम्न प्रकार से प्रभावी होंगे,

§ क § आस्ट्रिया में जिस कैलेंडर वर्ष में अनुसमर्थन प्रपत्रों का आदान-प्रदान होता है उसके अनुवर्ती किसी वित्तीय वर्ष में लगाए गए करों के संबंध में ।

§ ख § भारत में जिस कैलेंडर वर्ष में अनुसमर्थन प्रपत्रों का आदान-प्रदान होता है इसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात अथवा इसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

3. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए आस्ट्रिया गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच अभिसमय जिस पर 24 सितम्बर, 1963 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे वे पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार इस अभिसमय के उपबंधों के लागू हो जाने के बाद निष्प्रभावी हो जाएंगे ।

## अनुच्छेद - 29

## समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी सौविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के जून माह के तीसरे दिन अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यम से दूसरे सौविदाकारी राज्य को समापन का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी परिस्थिति में अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

§क§ आस्ट्रिया में जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती किसी द्वितीय वर्ष में लगाए गए कर्तों के संबंध में ;

§ख§ भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अक्षत के प्रथम दिन के पश्चात् अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्रधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने मौजूदा अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

ये वर्ष एक हजार नौ सौ निन्नानवे के नवम्बर माह के आठवें दिन, हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और इसके सभी पठ समान रूप से प्रमाणिक हैं । किसी भी पठ में अर्थ-भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पठ प्रमाणी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

आस्ट्रिया गणराज्य की  
सरकार की ओर से

ह./-

ह./-

प्रमोद महाजन

डॉ० बेनिता फेरेरी - वाल्डनर

### प्रेतोक्तेत

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पोरहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए आस्ट्रेलिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरियों ने निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति व्यक्त की है जो इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे।  
अनुच्छेद 6 और 13 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा गया है कि कमजोर भारत के मामले में अनुच्छेद 23, पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधधीन अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय और अचल सम्पत्ति के अंतरण पर प्राप्त पूंजीगत अभिलम्भों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है।  
अनुच्छेद 7 के संदर्भ में :

§क§ यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 में यथा-उल्लिखित मुख्यालय कार्यालय के खर्चों के बारे में कटौतियां उन कटौतियों से किसी भी हालत में कम नहीं होंगी जिनकी इस अभिसमय के लागू होने की तारीख को भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है

§ख§ आस्ट्रेलिया के मामले में इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लभ" पद में किसी साझेदारी में तथा व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय में भागीदारी से जिसे कर प्रयोजनार्थ उसी रूप में माना जाता है, तथा आस्ट्रेलियाई कानून के अंतर्गत सृजित किसी निष्क्रिय साझेदारी में भागीदारी से प्राप्त लभ शामिल हैं।  
अनुच्छेद 24 के संदर्भ में :

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित संस्थापन के लभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से रोकना है जो उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी किसी कंपनी के लभों पर लगाई जाती है और न ही इसका अर्थ यह होगा कि यह अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हो। तथापि, कर की दर में अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अनुच्छेद 26 के संदर्भ में :

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी सूचना के प्रकटीकरण के मामले में व्यक्ति-सम्बद्ध तथ्यों की गोपनीयता का वहां तक अधित्याग कर दिया जाए जहां तक कि यह किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्रमुख लोक-हितों के प्रमुख और वैध हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हो।

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 26, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ ग के उपबंधों में किसी राज्य द्वारा प्रदान किए गए मूलभूत अधिकार, विशेषकर तथ्य संरक्षण के क्षेत्र में, शामिल हैं।

जिसके साक्ष्य में, दोनों सौवदाकारी राज्यों के, इसके लिए विधिवत् रूप से प्रधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में वर्ष एक हजार नौ सौ नब्बानवे : नवम्बर माह के आठवें दिन, हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, इसके सभी पठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पठों के बीच अर्थ-निरूपण की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पठ प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

ह./-

प्रमोद महाजन

ऑस्ट्रिया गणराज्य की  
सरकार की ओर से

ह./-

डॉ० बेनिता फेरेरो-वाल्डनर

[अधिसूचना सं. 271/2001/फा. सं. 505/1/82-एफ.टी.डी.]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2001

#### INCOME-TAX

**G.S.R. 682(E).**— Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income shall enter into force, on the 5<sup>th</sup> September, 2001, thirty days after the exchange of Instruments of Ratification as required by paragraph 2 of Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

**Convention between the Government of the Republic of India  
and the Government of the Republic of Austria for  
the avoidance of double taxation and the  
prevention of fiscal evasion  
with respect to taxes on income**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Austria, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1

**PERSONS COVERED**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States

Article 2

**TAXES COVERED**

(1) This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied

(2) There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation

(3) The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular

(a) in Austria

- (i) the income tax (die Einkommensteuer),
- (ii) the corporation tax (die Körperschaftsteuer).

(hereinafter referred to as "Austrian taxes").

(b) in India

the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),

(hereinafter referred to as "Indian tax" )

(4) The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws

Article 3GENERAL DEFINITIONS

(1) For the purposes of this Convention unless the context otherwise requires -

- (a) the term "Austria" means the Republic of Austria.
- (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law including the U N Convention on the Law of the Sea,
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Austria or India as the context requires,
- (d) the term "fiscal year" means, -
  - (i) in relation to Austrian tax, the calendar year,
  - (ii) in relation to Indian tax, the financial year beginning on the first day of April,
- (e) the term "tax" means Austrian tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes,
- (f) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States,
- (g) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States,
- (h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State,
- (i) the term "competent authority" means, -
  - (i) in Austria, the Federal Minister of Finance or his authorised



representative.

(ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representatives.

(j) the term "national" means.

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State.

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State:

(k) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies

#### Article 4

#### RESIDENT

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein

(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows -

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him, if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode.

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement

(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement

#### Article 5

#### **PERMANENT ESTABLISHMENT**

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on

(2) The term "permanent establishment" includes especially:-

(a) a place of management,

(b) a branch,

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop,

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a sales outlet;

(h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

(i) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (for the

same or connected project, site or activities) continue for a period of more than six months.

(3) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include -

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise,
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery,
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise,
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise,
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character,
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person, other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies, is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if such a person

- (a) has, and habitually exercises, in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, or

(c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph

(7) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other

#### Article 6

### **INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY**

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property

(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### Article 7

### **BUSINESS PROFITS**

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, and according to the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

### **SHIPPING AND AIR TRANSPORT**

(1) Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

(2) Profits derived by an enterprise referred to in paragraph 1 which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

(3) For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

(4) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 9

### **ASSOCIATED ENTERPRISES**

(1) Where -

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other

#### Article 10

#### DIVIDENDS

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

### Article 11

### INTEREST

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2 -

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

- (i) the State, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State; or
- (iii) in the case of India also the Export-Import Bank of India; or
- (iv) in the case of Austria also the Oesterreichische Kontrollbank AG;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the State if it is derived and beneficially owned by any person (other than a person referred to in subparagraph a) who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the first-mentioned Contracting State.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income



from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### Article 12

#### **ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES**

(1) Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties and fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties and fees for technical services.

(3) The term "royalties" as used in this Article, means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or

for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

(5) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

### Article 13

### CAPITAL GAINS

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in

the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(4) Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State

(5) Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

(6) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### Article 14

### **INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

(1) Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:-

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve months; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants

Article 15**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: -

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve months, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17**ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS**

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in this capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or a sportsperson who is a resident of a Contracting State from personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in this capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

#### Article 18

### **PENSIONS AND ANNUITIES**

(1) Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

(2) The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

(3) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

#### Article 19

### **GOVERNMENT SERVICE**

- (1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who
- (i) is a national of that State, or
  - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services
- (2) The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to remuneration derived by members of permanent delegations of foreign commerce of a Contracting State in the other Contracting State
- (3) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State
- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State
- (4) The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to remuneration and pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof

#### Article 20

#### STUDENTS

- (1) A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on -
- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training, and
  - (b) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve month if the employment is directly related to his studies or apprenticeship
- (2) The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in

no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other State

#### Article 21

### **PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS**

(1) A professor or a teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State

(2) This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons

(3) For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State

#### Article 22

### **OTHER INCOME**

(1) Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State

Article 23ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

(1) The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where express provision to the contrary is made in this Convention.

(2) In the case of Austria double taxation shall be eliminated as follows:-

(a) Where a resident of Austria derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Austria shall, subject to the provisions of subparagraphs b) and c) exempt such income from tax.

(b) Where a resident of Austria derives items of income which, in accordance with the provisions of paragraphs 2 of Articles 10, 11, 12, paragraphs 4 and 5 of Article 13 and paragraph 3 of Article 22 may be taxed in India, Austria shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from India.

(c) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Austria is exempt from tax in Austria, Austria may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

(3) In the case of India, double taxation shall be eliminated as follows:-

(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Austria, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Austria whether directly or by deduction at source. Such amount shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Austria.

(b) Where, in accordance with any provision of this Convention, income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.



Article 24NON-DISCRIMINATION

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

(3) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the

293762/2001-7

first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

#### Article 26

### EXCHANGE OF INFORMATION

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:-

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

#### Article 27

### MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### Article 28

### ENTRY INTO FORCE

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force thirty days after the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:-

(a) in Austria, in respect of the taxes levied for any fiscal year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place.

(b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place.

(3) The Convention between the Republic of Austria and the Republic of India for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at New Delhi on 24th September, 1963, shall cease to have effect when the provisions of this Convention become effective in accordance with the provisions of paragraph 2.

#### Article 29

### TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect: -

a) in Austria, in respect of the taxes levied for any fiscal year following the calendar year in which the notice of termination is given.

b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate in Vienna on the 8<sup>th</sup> day of November, 1997 in the German, Hindi and English languages, each text being equally authentic. In the case of a divergence among the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of  
the Republic of India:

For the Government of  
the Republic of Austria:

Sd./-

Sd./-

**PRAMOD MAHAJAN**

**DR. BENITA FERRERO-WALDNER**

#### PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

#### Ad Articles 6 and 13:

With reference to paragraphs 1 of Article 6 and Article 13 it is understood that in the case of India income from immovable property and capital gains on alienation of immovable property respectively may be taxed in both Contracting States subject to the provisions of Article 23 paragraph 3.

#### Ad Article 7:

a) It is understood that the deductions in respect of the head office expenses as referred to in paragraph 3 of Article 7 shall in no case be less than those allowable under the Indian Income Tax Act as on the date of entry into force of this Convention.

b) In the case of Austria the term "profits" as used in this Article includes the profits derived by any partner from his participation in a partnership and in any other body of persons which is treated in the same way for tax purposes and from a participation in a sleeping partnership (Stille Gesellschaft) created under Austrian law.

#### Ad Article 24

It is understood that the provisions of Article 24 paragraph 2 shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. However the difference in tax rate shall not exceed 15 percentage points.

#### Ad Article 26

It is understood that in the case of disclosure of information referred to in paragraph 1 of Article 26 the confidentiality of person related data may be waived only insofar as this is necessary to safeguard predominant and legitimate interests of another person or predominant public interests.

It is understood that the provisions of Article 26 paragraph 2 subparagraph c) include the basic rights granted by a State, in particular in the area of data protection.

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate in *Vienna* on the *8<sup>th</sup>* day of *November 1999*,  
in the German, Hindi and English languages, each text being equally authentic. In the case  
of a divergence among the texts the English text shall be the operative one.

For the Government of  
the Republic of India:

Sd./-

PRAMOD MAHAJAN

For the Government of  
the Republic of Austria:

Sd./-

DR. BENITA FERRERO-WALDNER

[Notification No. 271/2001/F. No. 505/1/82-FTD]

VIJAY MATHUR, Jt. Secy.

